

**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की दिनांक
04 दिसम्बर, 2017 को सम्पन्न 25वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की 25वीं बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को मुख्य सचिव, उम्प्रो शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि डॉ आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव, (सी० एण्ड सी०), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली तथा प्रदेश के कृषि एवं समर्गीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/उच्चाधिकारियों एवं कृषि विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रमुख सचिव (कृषि) द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया। तदोपरान्त कृषि निदेशक, उम्प्रो द्वारा एजेण्डावार विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा एजेण्डावार दिए गए निर्णयों/निर्देशों का विवरण निम्नवत् है:-

1. एस०एल०एस०सी० की गत बैठक दिनांक 03.07.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति को अवगत कराया गया कि एस०एल०एस०सी० की गत बैठक दिनांक 03.07.2017 को सम्पन्न हुई थी। बैठक का कार्यवृत्त शासन के पत्र संख्या-714/12-3-2017-199/2007 टी.सी. दिनांक 20.07.2017 के द्वारा समिति के समस्त सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। कार्यवृत्त के किसी भी प्रस्तर/अंश के संदर्भ में किसी भी स्तर से कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। तदोपरान्त समिति की बैठक दिनांक 03.07.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. समिति की गत बैठक के कार्यवृत्त में लिए गए निर्णयों पर परिपालन की स्थिति

समिति को अवगत कराया गया कि एस०एल०एस०सी० की दिनांक 03.07.2017 में दिए गये निर्णयों एवं निर्देशों के अनुसार कार्यवृत्त के सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कराते हुए परिपालन कराया गया है। समिति द्वारा प्रस्तरवार परिपालन की स्थिति का संज्ञान लिया गया।

3. योजना की प्रगति की स्थिति

I— वर्ष 2017-18 में गत वर्ष की अप्रयुक्त पुनर्वैध धनराशि रु० 176.54 करोड़ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार स्तर से पूर्व निर्गत एलोकेशन रु० 736.13 करोड़ में भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.11.2017 के क्रम में ए.एफ.डी.पी. उपयोजना हेतु अनुमोदित धनराशि रु० 7.20 करोड़ (केन्द्रांश रु० 4.32 करोड़ एवं राज्यांश रु० 2.88 करोड़) को सम्मिलित करते हुए अब तक रु० 733.33 करोड़ की धनराशि का

मात्राकरण प्राप्त है। वर्ष 2017–18 के लिए गत वर्ष की पुनर्वेध धनराशि ₹0 176.54 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल ₹0 909.87 करोड़ की उपलब्धता सम्भावित है। भारत सरकार के स्तर से केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में ₹0 217.52 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसमें 40 प्रतिशत राज्यांश ₹0 145.01 करोड़ को सम्मिलित करते हुए ₹0 365.53 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है। इस धनराशि में गत वर्ष की पुनर्वेध धनराशि ₹0 176.54 करोड़ को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में कुल ₹0 539.07 करोड़ की धनराशि वित्तीय स्वीकृतियों हेतु उपलब्ध है।

II— उपरोक्त के सापेक्ष अब तक ₹0 429.96 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियों कार्यदायी विभागों के पक्ष में निर्गत की जा चुकी है। सम्बन्धित विभागों द्वारा मात्र ₹0 156.47 करोड़ (36 प्रतिशत) का व्यय कराया गया है। समिति द्वारा विभागवार प्रगति का संज्ञान लिया गया तथा योजना की कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही सम्बन्धित विभाग दिनाँक 15.12.2017 तक पुनर्वेध धनराशि का शत-प्रतिशत तथा वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष 60 प्रतिशत धनराशि का दिनाँक 15.12.2017 तक व्यय कराते हुए नोडल विभाग (कृषि विभाग) को उपभोग प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। नोडल विभाग द्वारा संकलित उपभोग प्रमाण—पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किश्त अवमुक्त कराने की कार्यवाही माह दिसम्बर 2017 के अन्त तक सुनिश्चित करायी जायेगी।

III— समिति द्वारा कतिपय विभागों यथा कृषि विभाग की 30 प्रतिशत, पशुपालन विभाग की 28 प्रतिशत, रेशम विभाग की 04 प्रतिशत एवं मत्स्य विभाग की 15 प्रतिशत प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभाग भारत सरकार स्तर से द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार व्यय कराते हुए दिनाँक 15.12.2017 तक नोडल विभाग को उपयोगिता प्रमाण—पत्र उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा पशुधन विकास परिषद तथा ₹0.000.000 की शून्य प्रगति पर रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित संस्थायें तत्कालिक रूप से धनराशि के शत-प्रतिशत व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

IV— वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी हेतु 59.43 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एस.सी.पी. कम्पोनेन्ट) हेतु 40.44 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी. कम्पोनेन्ट) के लिए 0.13 प्रतिशत का एलोकेशन एवं तदनुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है। वर्तमान में एस.सी.पी. कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत ₹0 124.35 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी विभागों के स्तर से मात्र ₹0 25.50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत की जा सकी है। समिति द्वारा स्थिति का संज्ञान लिया गया तथा निर्देश दिये गये कि समस्त

विभाग/संस्थाए भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2017-18 में संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत राजस्व एवं पैूजीगत मदों में ग्राण्टवार धनराशि की माँग एवं व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

4. पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार:-

समिति के समक्ष पूर्व में एस०एल०एस०सी० से अनुमोदित कतिपय परियोजनाओं में प्रस्तावित संशोधनों का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिये गये निर्णयों/निर्देशों का विवरण निम्नवत है:

1. कृषि विभाग :-

i. **Integrated Cereal Development Programme-Wheat** परियोजना लागत रु० 4500.00 लाख :- वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश के 39 नॉन-एन०एफ०एस०एस०/बी०जी०आर०ई०आई० जनपदों में गेहू के उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों के वितरण पर रु० 1000 प्रति कु० अनुदान की दर पर तीन लाख कु० गेहू बीज वितरण की योजना हेतु एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक 03.07.2017 में रु० 3000.00 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है। वर्तमान में कृषकों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत गेहू के प्रमाणित बीजों के लक्ष्य 3.00 लाख कु० से बढ़ाकर 4.50 लाख कु० किये गये हैं। लक्ष्यों में वृद्धि के अनुसार अब योजना की लागत रु० 4500.00 लाख हो गयी है। एस०एल०पी०एस०सी० की अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा परियोजना को एन.एफ.एस.एम. के कास्ट नार्स पर वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। तदोपरान्त समिति द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु संशोधित कार्ययोजना लागत रु० 4500.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा :-

i. **Construction of fencing at Sehlamau farm (Phase-II) under SIMA** परियोजना लागत रु० 236.82 लाख :- परियोजना हेतु एस०एल०एस०सी० की बैठक दिनांक 21.11.2016 में रु० 211.60 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गई। शासन के स्तर से नामित कार्यदायी संस्था “राजकीय निर्माण निगम” द्वारा जी०एस०टी० प्रभावी होने के पश्चात रु० 236.82 लाख के संशोधित आगणन प्रस्तुत किये गये हैं। एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 31.10.2017 में प्रस्ताव को एस.एल.एस.सी. के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा परियोजना को

जी.एस.टी. की वर्तमान प्रचलित/प्रभावी दरों पर वृद्धि के साथ वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। तदनुसार समिति द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जी.एस.टी. की प्रभावी दरों पर अनुमत्य करते हुए संशोधित कार्ययोजना लागत ₹0 236.82 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

- ii. Construction of fencing at Rehmankhera farm (Phase-III) under SIMA परियोजना लागत ₹0 36.16 लाख :—परियोजना हेतु एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 21.11.2016 में ₹0 32.31 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गई। शासन के स्तर से नामित कार्यदायी संस्था ‘राजकीय निर्माण निगम’ द्वारा जी0एस0टी0 प्रभावी होने के पश्चात ₹0 36.16 लाख के संशोधित आगणन प्रस्तुत किये गये हैं। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 31.10.2017 में प्रस्ताव को एस.एल.एस.सी. के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा परियोजना को जी.एस.टी. की वर्तमान प्रचलित/प्रभावी दरों पर वृद्धि के साथ वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। तदनुसार समिति द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जी.एस.टी. की प्रभावी दरों पर अनुमत्य करते हुए संशोधित कार्ययोजना लागत ₹0 36.16 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विविधि एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा :—

- i. **Cost escalation due to GST-** विश्वविद्यालय की एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 21.11.2016, 20.12.2016 एवं 03.07.2017 में निर्माण कार्य-परक ₹0 2544.09 लाख लागत की 08 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्यों पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 06 प्रतिशत सर्विस टैक्स के स्थान पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की मांग की जा रही है। इस कारण से परियोजनाओं की लागत में ₹0 77.86 लाख की मूल्य वृद्धि हुई है। समिति द्वारा जी0एस0टी0 की प्रभावी दरों के अनुसार परियोजनावार एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में एस0एल0पी0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ संस्तुत संशोधित लागत का विवरण निम्नवत् है :—

धनराशि ₹0 लाख में

S.N.	Project name	SLSC approval date	Component	Approved by SLSC	Revised due to GST
1	2	3	4	5	6
1	Propagation of insemination techniques in goats and establishment of semen bank for enhanced productivity and socio-economic upliftment	21.11.16	Civil work	99.74	105.39
			Other item	206.76	206.76
			Total	306.50	312.15
2	Unit of Silage making and popularization of low cost silage technology for year round fodder availability for small scale farmers	21.11.16	Civil work	22.84	24.13
			Other item	66.78	66.78
			Total	89.62	90.91
3	Establishment of modernized goat farm for strengthening goat husbandry practices in U.P.	20.12.16	Civil work	160.13	169.19
			Other item	279.92	279.92
			Total	440.05	449.11

S.N.	Project name	SLSC approval date	Component	Approved by SLSC	Revised due to GST
1	2	3	4	5	6
4	Establishment of environment controlled chamber and calorimetric unit to enhance productivity of livestock in the scenario of climate change in U.P.	20.12.16	Civil work	135.00	142.64
			Other item	117.50	117.50
			Total	252.50	260.14
5	Establishment of small scale feed processing demonstration unit to promote rural youth entrepreneurship	03.07.17	Civil work	74.34	78.27
			Other item	158.00	158.00
			Total	232.34	236.27
6	Strengthening and modernization of University farm	03.07.17	Total (Civil work)	877.68	924.02
7	Strategic control of subclinical parasitism for better animal health and enhanced productivity in U.P.	03.07.17	Civil work	40.00	42.11
			Other item	82.20	82.20
			Total	122.20	124.31
8	Strengthening of clinical diagnostic and therapeutic facilities at University referral hospital for benefit of farmers and livestock owners	03.07.17	Civil work	35.00	36.84
			Other item	188.20	188.20
			Total	223.20	225.04
Total				2544.09	2621.95

उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा प्रस्ताव को जी.एस.टी. की वर्तमान प्रचलित/प्रभावी दरों पर वृद्धि के साथ वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा जी.एस.टी. की प्रभावी दरों पर अनुमन्य करते हुए परियोजनावार उक्त तालिका के कालम-06 के अनुसार परियोजनावार संशोधित लागत का अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. गन्ना विभाग :-

- i. **Enhancing sugarcane production in U.P. परियोजना लागत ₹0 1729.12**
लाख:-परियोजना हेतु एस०एल०एस०सी० की बैठक दिनांक 03.07.2017 में गन्ना विभाग के प्रस्तावानुसार ₹0 1729.12 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गई थी, जिसके अन्तर्गत ड्रिप इरीगेशन प्रणाली के 1000 हेठों में प्रदर्शनों हेतु ₹0 500.00 लाख का अनुमोदन प्राप्त है। वर्तमान में गन्ना विभाग द्वारा ड्रिप इरीगेशन प्रणाली कार्यमद की धनराशि ₹0 500.00 लाख को कृषि यन्त्रों हेतु परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया गया है। एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में परियोजना की अनुमोदित कार्ययोजना लागत ₹0 1729.12 लाख के अन्तर्गत ही ड्रिप-इरीगेशन प्रणाली कार्यमद की धनराशि ₹0 500.00 लाख को कृषि यन्त्र मद में परिवर्तित करने हेतु एस०एल०एस०सी० के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा प्रस्ताव एन.एफ.एस.एम./एस.ए.ए.एम. के नाम्स पर वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा भारत सरकार के अभियान के अनुसार गन्ना की फसल के लिए उपयुक्त/संस्तुत कृषि यन्त्रों का वितरण डी.बी.टी. के माध्यम से कराने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. सहकारिता विभाग :-

i. Construction of PACS Go-down परियोजना हेतु वर्ष 2014–15 में ₹ 6700.10 लाख की धनराशि सहकारिता विभाग के पक्ष में निर्गत की गई, जिसके सापेक्ष ₹ 6600.00 लाख का व्यय कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक ₹ 100.10 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपेक्षित हैं। सहकारिता विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्गत धनराशि ₹ 6700.10 लाख के सापेक्ष 303 गोदामों का निर्माण कराया जाना था। कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा 297 गोदामों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है तथा 06 गोदामों यथा— फिरोजाबाद-01, आजमगढ़-01, बलिया-01, जौनपुर-01 एवं इलाहाबाद-02 में निर्माण स्थलों के सम्बन्ध में स्थानीय विवादों एवं मात्र उच्च न्यायालय विचाराधीन होने के कारण कार्य बाधित हैं। जनपद आजमगढ़ के निर्माण स्थल पर ₹ 7.06 लाख के कार्य करा लिए गए हैं तथा जनपद बलिया के गोदाम निर्माण हेतु ₹ 3.26 लाख की निर्माण सामग्री का उपयोग अन्यत्र कराया जाना है। इस प्रकार, ₹ 114.54 लाख की धनराशि उपलब्ध है। उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत ₹ 27.49 लाख प्रति गोदाम की दर से 04 गोदाम ही निर्मित कराये जा सकते हैं। एस.एल.पी.एस.सी.0 की बैठक दिनांक 31.10.2017 में सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में निर्मित समस्त गोदामों पर कृषि उत्पाद विनियम अधिनियम के तहत “भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण—WDRA (Warehousing Development and Regulatory Authority) से प्रमाणन कराते हुए कृषकों को भण्डारण की सुविधा सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत 04 गोदामों का निर्माण पूर्ण कराने हेतु एस.एल.पी.एस.सी.0 के अनुमोदनार्थ संस्तुति की गई हैं। भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा प्रस्तावित नवीन 04 गोदामों के निर्माण स्थल का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश के साथ सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा एस.एल.पी.एस.सी. एवं भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार प्रस्तावित नवीन 04 गोदामों के निर्विवाद निर्माण स्थल का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. वर्ष 2017–18 हेतु नवीन परियोजना प्रस्तावों पर विचार :-

अ— समिति के समक्ष कृषि एवं सम्बर्गीय विभागों के द्वारा ₹ 14107.55 लाख (01 से 03 वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 10158.23 लाख की एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में संस्तुत परियोजनायें प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागवार/ परियोजनावार दिए गए निर्णयों/निर्देशों का विवरण निम्नवत है:-

1. कृषि विभाग :-

- i. **Pico-projectors and hand held devices for SMAE sub-mission of ATMA project** परियोजना लागत ₹0 668.30 लाख :- प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में आत्मा योजनान्तर्गत 02 पीको प्रोजेक्टर प्रति विकास खण्ड एवं प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 45 हैन्डहेल्ड डिवाइस क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रसार कार्यों हेतु उपलब्ध कराये जाने हैं। इस प्रकार कुल 1642 पीको प्रोजेक्टर एवं 3375 हैन्डहेल्ड डिवाइस की आवश्यकता है। पीको प्रोजेक्टर एवं हैन्डहेल्ड डिवाइस की 50 प्रतिशत आर0के0वी0वाई0 एवं 50 प्रतिशत आत्मा योजना की निधियों से व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 821 पीको प्रोजेक्टर एवं 1688 हैन्डहेल्ड डिवाइस के क्रय हेतु ₹0 668.30 लाख की कार्य योजना एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में भारत सरकार के अभिमत/ सहमति के साथ कार्ययोजना लागत ₹0 668.30 लाख को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा ₹0 0.30 लाख प्रति पीको प्रोजेक्टर एवं प्रति हैन्डहेल्ड डिवाइस हेतु प्रस्तावित ₹0 0.25 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹0 0.20 लाख की सीमा हैन्डहेल्ड डिवाइस हेतु संस्तुति की गयी है। तदनुसार समिति द्वारा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना लागत ₹0 583.90 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ii. **Scheme for promoting non-loanee farmers for Pradhan Mantri Fasal Beema Yojna in U.P.** परियोजना लागत ₹0 100.00 लाख :- प्रदेश के 20 लाख नॉन-लोनी फारमस को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने हेतु आत्मा योजनान्तर्गत नॉन-लोनी फारमस को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने हेतु आत्मा योजनान्तर्गत कार्यरत 2463 बी.टी.एम./ए.टी.एम. को ₹0 10.00 प्रति कृषक प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 ₹0 100.00 लाख को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। ₹0 100.00 लाख को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा आर0के0वी0वाई0 की गाइड लाइन्स की सीमा तक वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा नॉन-लोनी कृषकों को पी.एम.एफ.बी.वाई. योजना से जोड़ने के साथ-साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित कराने के सार्थक प्रयास करने के निर्देश भी दिये गये। सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा कार्ययोजना लागत ₹0 100.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 के लिए प्रदान किया गया।
- iii. **Drip and sprinkler solar lift irrigation system for benefit of farmers in salty water affected area in Etah district** परियोजना लागत ₹0 78.34 लाख :- एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में एटा जनपद के सकीट विकास खण्ड के सराय जवाहरपुर ग्राम में 50 हेक्टेक्टर हेतु 01 ड्रिप एवं सोलर लिफ्ट इरीगेशन यूनिट की स्थापना के लिये आर0के0वी0वाई0 अंश (90 प्रतिशत) के रूप में ₹0 78.34 लाख की कार्ययोजना एस.एल.एस.सी. के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को पी.एम.के.एस.वाई./एन.एफ.एस.एम. के नाम्स पर वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया

गया है। समिति द्वारा कार्ययोजना लागत ₹0 78.34 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 के लिए प्रदान किया गया।

iv **The Millions Farmers School "Kisan Pathshala"** परियोजना लागत ₹0 617.00 लाख :— समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों की 15500 ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत 05 दिवसीय किसान पाठशालाओं का आयोजन रबी 2017 में किया जाना है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के 100 तकनीकी कार्मिकों प्रति जनपद की दर से कृषि विज्ञान केन्द्रों पर 01 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जायेंगे। प्रारम्भिक रूप से आगणित धनराशि के अनुसार कार्ययोजना लागत ₹0 307.50 लाख को वर्ष 2017-18 के लिए एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में की गयी थी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2017 में आयोजित प्री-एस0एल0एस0सी0 की बैठक में संशोधित कार्ययोजना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तदकम में संशोधित कार्ययोजना ₹0 617.00 लाख निदेशालय के पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में परियोजनान्तर्गत ₹0 12.50 लाख कृषकों को कृषि तकनीक बुलेटिन, ₹0 700.00 प्रति कृषि पाठशाला बैनर एवं दरी आदि की व्यवस्था हेतु तथा ₹0 500.00 प्रति पाठशाला उद्घाटन तथा ₹0 500.00 प्रति पाठशाला समापन दिवस के आयोजनों हेतु प्रस्तावित है। इस प्रकार, अब ₹0 462.00 लाख की आवश्यकता है। समस्त प्रदेश में अभियान स्वरूप किसान पाठशालाओं का दिनांक 05.12.2017 से शुभारम्भ किया जा रहा है। संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा परियोजना पर सहमति प्रदान की गई। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कार्ययोजना लागत ₹0 462.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान किया गया।

2. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग :-

- i. **Establishment of Hi-tech vegetable nursery to boost vegetable production**
परियोजना लागत ₹0 3202.92 लाख :— परियोजनान्तर्गत प्रदेश के 11 जनपदों यथा गोरखपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, कौशाम्बी, हापुड़, फैजाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, झौंसी एवं बहराइच में उद्यान विभाग के राजकीय प्रक्षेत्र एवं पौधशालाओं पर उच्च तकनीकी विधि से सब्जियों की फसलों की पौध तैयार कराकर कृषकों को उपलब्ध कराने तथा सब्जियों की खेती के क्षेत्र विस्तार हेतु ₹0 3202.92 लाख की कार्ययोजना प्रस्तावित की गयी है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनांक 31.10.2017 परियोजना लागत ₹0 3202.92 लाख को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को एम0आई0डी0एच0/आर0के0वी0वाई0 एवं पी0एम0के0एस0वाई0 के नाम्स पर नान-एन0एच0एम0 जनपदों हेतु सपोर्ट किया गया है। नियोजन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इंगित किया गया कि नर्सरियों के रख-रखाव एवं नियमित संचालन की व्यवस्था उद्यान विभाग द्वारा किस प्रकार की जाएगी, यह तथ्य स्पष्ट नहीं किए गए हैं। प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विभागीय बजट से ही नर्सरियों का रख-रखाव आदि

किया जाएगा। तदनुसार समिति द्वारा प्रस्तावित 11 जनपदों में से 03 नॉन-एनोएच०एम० जनपदों हेतु ₹0 873.52 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 के लिए प्रदान किया गया।

ii. Development of bee-keeping in U.P. परियोजना लागत ₹0 1063.50 लाख:- परियोजनान्तर्गत प्रदेश के 45 जनपदों में 1125 मधुमक्खी पालन इकाईयों (25 इकाई प्रति जनपद) की स्थापना एम.आई.डी.एच. के कास्ट नाम्स पर समिति द्वारा इकाईयों की जानी है। एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 31.10.2017 में ₹0 1063.50 लाख की कार्ययोजना को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई है कि राज्य स्तर से परियोजना प्रस्तुत करने से पूर्व इन्टीग्रेटेड बी-कीपिंग डेवलपमेंट सेन्टर (IBDC) की स्थापना कराई जाए। समिति द्वारा सम्यक् विचोरणप्राप्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार वांछित सूचनाओं सहित प्रस्ताव प्रेषित करने तथा सकारात्मक अभिमत दिनांक 31.12.2017 तक प्राप्त करने के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत ₹0 1063.50 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान किया गया।

iii. Allocation of fund for VIUC Sub-scheme from Normal RKVY :- समिति को अवगत कराया गया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित आर०के०वी०वाई० की Vegetable Initiatives for Urban Clusters (VIUC) उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में उपलब्ध पुनर्वैध धनराशि ₹0 387.13 लाख (शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) के सापेक्ष ₹0 382.50 लाख की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 28.03.2017 के द्वारा उद्यान विभाग के पक्ष में निर्गत की गई। उद्यान विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2017 को ₹0 35.70 लाख के बिल कोषागार को प्रेषित किए गए, जिनका टोकन लैप्स होने के कारण धनराशि लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित नहीं हो सकी। फलस्वरूप सम्पूर्ण धनराशि विभाग द्वारा समर्पित कर दी गई। वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोजना की अप्रयुक्त धनराशि ₹0 387.13 लाख का रिवैलीडेशन नहीं किया गया, अपितु निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि भारत सरकार को समर्पित कर दी जाए। वर्तमान में उद्यान विभाग द्वारा ₹0 30.525 लाख की मांग गत वर्ष संपादित कार्यों की देनदारियों हेतु की गई है। एस०एल०पी०एस०सी० की बैठक दिनांक 31.10.2017 में आर०के०वी०वाई० सामान्य की निधियों से ₹0 30.525 लाख के मात्राकरण के संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि Naturally Ventilated Green House की प्रस्तावित दरें उच्चतम् हैं, जिनके संशोधन की आवश्यकता है, तदनुसार कार्यवाही के करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को एम०आई०डी०एच० के कास्ट नाम्स पर सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा एम०आई०डी०एच० के कास्ट नाम्स पर आर०के०वी०वाई०-सामान्य के अन्तर्गत वित्त पोषण करने के निर्देश के साथ ₹0 30.53 लाख का वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. पशुपालन विभाग :-

लाख का अनुमादन प्रदान किया गया।

ii. Brucellosis vaccination in bovine परियोजना लागत ₹0 57.75 लाख:-

परियोजनान्तर्गत समस्त जनपदों 50000 सॉडों (Bovine) प्रति वर्ष के टीकाकरण कार्य हेतु ₹0 57.75 लाख (03 वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹0 19.25 लाख की कार्ययोजना ₹0 57.75 लाख (03 वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹0 19.25 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है। परियोजना के अन्तर्गत ₹0 32.00 प्रति वैक्सीन लागत एवं ₹0 6.50 प्रति टीकाकरण के रूप में प्रस्तावित है। एस.एल.एस.सी.0 की बैठक दिनांक 31.10.2017 में ₹0 57.75 लाख (03 वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹0 19.25 लाख की कार्ययोजना को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग भारत सरकार का अभिमत प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार का सकारात्मक अभिमत दिनांक 31.12.2017 तक प्राप्त करने के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत ₹0 57.75 लाख (03 वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹0 19.25 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

iii. Glanders and Farcy disease surveillance scheme परियोजना लागत रु0 327.39 लाख :- परियोजनान्तर्गत समस्त जनपदों में घोड़ा प्रजाति के पशुओं में होने वाली ग्लैण्डर एवं फारसी बीमारी एक घातक समस्या है। बीमार पशु के सम्पर्क में आने में यह बीमारी मनुष्यों में भी हो सकती है। ग्लैण्डर एवं फारसी बीमारी की रोकथाम एवं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रु0 327.39 लाख (02 वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु रु0 190.56 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है। एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में रु0 327.39 लाख (02 वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु रु0 190.56 लाख की कार्ययोजना को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति

की गयी है। भारत सरकार द्वारा डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग भारत सरकार का अभियान प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत भारत सरकार का सकारात्मक अभियान दिनांक 31.12.2017 तक प्राप्त करने के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत ₹0 327.39 लाख (02 वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹0 190.56 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ :-
- i. Establishment of advance diagnostic laboratory for identification of livestock diseases in Western U.P. परियोजना लागत ₹0 291.00 लाख :- विश्वविद्यालय द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारियों के निदान हेतु प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है। परियोजनान्तर्गत पूर्व निर्मित भवन का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा आवश्यक उपकरण आदि हेतु ₹0 291.00 लाख की आवश्यकता है। परियोजना को आई.सी.ए.आर. द्वारा वित्त पोषण हेतु संस्तुत किया गया है। एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोगशाला में कृषकों को रियायती दरों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। इस आशय की वचनबद्धता कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के द्वारा नोडल विभाग (कृषि विभाग) को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदन के पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी। कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 24.11.2017 के द्वारा एस.एल.पी.एस.सी. के निर्देशानुसार वचनबद्धता उपलब्ध करा दी गयी है। भारत सरकार द्वारा आई.सी.ए.आर. के अभियान के अनुसार परियोजना को वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹0 291.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान किया गया।
 - ii. Establishment of goat unit for conservation and revitalization of superior germplasm of Barbari goat परियोजना लागत ₹0 141.00 लाख :- विश्वविद्यालय में बरबरी प्रजाति की बकरियों के संरक्षण एवं पुनरोद्धार हेतु (50 मादा तथा 05 नर बकरियों) इकाई की स्थापना की जानी है। परियोजनान्तर्गत पूर्व निर्मित भवन का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा आवश्यक उपकरण आदि हेतु ₹0 141.00 लाख की आवश्यकता है। परियोजना को आई.सी.ए.आर. द्वारा सी.आई.आर.जी.० मखदूम (मथुरा) से शुद्ध नस्ल की बकरियां क्य करने के निर्देश के साथ वित्त पोषण की संस्तुति की गयी है। एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में कार्ययोजना लागत ₹0 141.00 लाख को वर्ष 2017-18 के लिए एस.एल.पी.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा भी परियोजना का सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹0 141.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान किया गया।

4. सैम हिंगिनबाटम यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलोजी एण्ड साइंसेज, इलाहाबाद :—
- Development of Barren and water scared land through afforestation and agroforestry system in district Allahabad** परियोजना लागत ₹0 171.00 लाखः— विश्वविद्यालय द्वारा फेंसिंग, सिंचाई सुविधाएं, आफिस भवन निर्माण, छोटे कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, भू—जल संरक्षण एवं ग्रीन हाउस फेन एण्ड पैड सिस्टम आदि कार्य किये जाने हैं। साथ ही परियोजना के अन्तर्गत कृषकों के 50 हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि वानिकी का माडल विकसित किया जायेगा। एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में परियोजना लागत ₹0 171.00 लाख (तीन वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017–18 हेतु ₹0 93.70 लाख की संस्तुति एस.एल.पी.एस.सी.0 के अनुमोदनार्थ की गयी है। भारत सरकार द्वारा आई.सी.ए.आर. के अभिमत के अनुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा के साथ परियोजना को वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.11.2017 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत संशोधित कार्ययोजना के अनुसार अन्तिम रूप से सपोर्ट कर दिया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹0 171.00 लाख (तीन वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2017–18 हेतु ₹0 93.70 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
5. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विविधि, कानपुर :—
- Role of lignocellulolytic bio-agents in decomposition of agro-residues to produce value added bio-fertilizer** परियोजना लागत ₹0 50.00 लाख :— जैव उर्वरक की उर्वरता में वृद्धि हेतु Lignocellulolytic bio-agents की भूमिका के शोध कार्यों हेतु पूर्व निर्मित प्रयोगशाला के सुदृढीकरण एवं आवश्यक उपकरणों के कार्य वर्ष 2017–18 में कराने हेतु ₹0 50.00 लाख की कार्ययोजना एस.एल.पी.एस.सी.0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को वित्त पोषण हेतु सपोर्ट नहीं किया गया है तथा अपेक्षा की गयी है कि राज्य द्वारा आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली का अभिमत प्राप्त कर लिया जाय। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत परियोजना के सम्बन्ध में आई.सी.ए.आर.0 नई दिल्ली का सकारात्मक अभिमत दिनांक 31.12.2017 तक प्राप्त करने के निर्देश के साथ कार्य योजना लागत ₹0 50.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
6. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी :—
- Conservation of elite indigenous breeds of cows using modern techniques and surrogacy** परियोजना लागत ₹0 2755.30 लाख :— परियोजना के अन्तर्गत देशी नस्ल की अभिजात वर्गीय गायों की प्रजाति को आधुनिक सेरोगेसी तकनीकी के उपयोग से संरक्षित करने हेतु परियोजनान्तर्गत पशुबाड़े, दुग्ध पार्लर एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु भवन निर्माण, आवश्यक उपकरण एवं पशुओं हेतु दवा आदि के लिए ₹0 2755.30 लाख (तीन वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2017–18 हेतु ₹0 2000.00 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।

एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में परियोजनान्तर्गत कृषकों को न्यूनतम दरों पर उन्नत किस्म की नस्ल की संतति उपलब्ध कराने सम्बन्धी वचनबद्धता एस.एल.एस.सी. के अनुमोदन से पूर्व नोडल विभाग (कृषि विभाग) को उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ रु0 2755.30 लाख (तीन वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु रु0 2000.00 लाख की कार्ययोजना को एस.एल.एस.सी.0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 27.11.2017 के द्वारा दी गयी वचनबद्धता में परियोजना अवधि तक कृषकों को पशुओं में भ्रूण प्रतिस्थापन तकनीकी की सुविधायें निःशुल्क दी जायेगी का उल्लेख किया गया है, जबकि एस.एल.पी.एस.सी. द्वारा विकसित सुविधाओं का कृषकों को न्यूनतम दरों पर लाभ उपलब्ध कराते रहने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार द्वारा परियोजना को आई.सी.ए.आर. की संस्तुति दिनांक 25.07.2016 के अनुसार वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत एस.एल.पी.एस.सी. एवं भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत रु0 2755.30 लाख (तीन वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017-18 हेतु रु0 2000.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विभिन्न एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा :-

i- Establishment of semen analytical laboratory for semen certification quality assurance of breeding buck semen परियोजना लागत रु0 169.00 लाख:- परियोजना के अन्तर्गत पशुओं के वीर्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु आवश्यक निर्माण कार्य एवं अन्य आवश्यक उपकरणों हेतु रु0 169.00 लाख की कार्ययोजना वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित की गई है। एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.17 में कार्ययोजना लागत रु0 169.00 लाख को एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा आई.सी.ए.आर. की संस्तुति के अनुसार परियोजना को वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत परियोजना लागत रु0 169.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान किया गया।

8. इन्टरनेशल काप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), हैदराबाद :-

i- KISAN-MITRA Knowledge-based Integrated Sustainable Agriculture Network- Mission India for Transforming Agriculture: Doubling Farmers Income in Bundelkhand, U.P. परियोजना लागत रु0 2823.60 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में 35000 हेठो (5000 हेठो प्रति जनपद) फसल विविधीकरण प्रदर्शन, आन-फार्म एक्शन रिसर्च, स्वायत्त हैत्य मैपिंग कार्ड तैयार एवं वितरण कराना, आन-लाइन मॉनीटरिंग, मूल्य संवर्धन मार्केट लिंकेज विकास, वर्कशाप, प्रशिक्षण, प्रक्षेत्र दिवस आयोजन व एक्सपोजर विजिट तथा स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में वृद्धि लाने

हेतु कार्यकर्मों के लिए ₹0 2823.60 लाख (तीन वर्षों के लिए) एवं वर्ष 2017–18 हेतु ₹0 988.80 लाख की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। परियोजना का क्रियान्वयन इन्टरनेशल क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), हैदराबाद, कृषि विभाग एवं स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा। एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनांक 31.10.2017 में कार्ययोजना लागत ₹0 2823.60 लाख (तीन वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2017–18 हेतु ₹0 988.80 लाख को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। भारत सरकार द्वारा परियोजना को सपोर्ट नहीं किया गया है तथा अपेक्षा की गयी है कि राज्य द्वारा आई.सी.ए.आर. का अभिमत प्राप्त कर लिया जाय। बैठक में संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा परियोजना पर सहमति प्रदान की गई। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹0 2823.60 लाख (तीन वर्ष के लिए) एवं वर्ष 2017–18 हेतु ₹0 988.80 लाख का अनुमोदन का आई.सी.ए.आर. के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ प्रदान किया गया।

5ब. समिति के समक्ष कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के एस.एल.एस.सी. की गत बैठक दिनांक 03.07.2017 में आई.सी.ए.आर.के अभिमत प्राप्त करने के निर्देश के साथ स्थगित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। बैठक में संस्थावार/परियोजनावार हुए विचार-विमर्श एवं दिए गए निर्देशों/निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :-

1. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर :-

- Strengthening of vegetable research station, Kalyanpur, Kanpur परियोजना** लागत ₹0 180.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में विश्वविद्यालय की परियोजना लागत ₹0 180.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई0सी0ए0आर0 के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तदक्रम में आई.सी.ए.आर. के पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा अन्तिम रूप से संशोधित कार्ययोजना के अनुसार वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। तदनुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा परियोजना को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹0 180.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017–18 हेतु प्रदान किया गया।
- Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in UP.** परियोजना लागत ₹0 44.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में विश्वविद्यालय की परियोजना लागत ₹0 44.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई0सी0ए0आर0 के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

भारत सरकार द्वारा परियोजना की संशोधित कार्ययोजना आई.सी.ए.आर. को उपलब्ध कराते हुए अन्तिम अभिमत प्राप्त करने तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम एम.आई.डी.एच., प्रक्षेत्र दिवस, एक्सपोज़र विजिट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मा के नाम्स पर कराने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा अन्तिम रूप से संशोधित कार्ययोजना के अनुसार वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹0 37.10 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान किया गया।

- iii. Strengthening of Rabi cereal for development of high yielding wheat & barley varieties and their agro-techniques परियोजना लागत ₹0 163.30 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में विश्वविद्यालय की परियोजना लागत ₹0 160.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई.सी.ए.आर. के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार द्वारा परियोजना की संशोधित कार्ययोजना आई.सी.ए.आर. को उपलब्ध कराते हुए अन्तिम अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा अन्तिम रूप से संशोधित कार्ययोजना लागत ₹0 163.30 लाख (02 वर्षों के लिये) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹0 98.30 लाख के वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹0 163.30 लाख (02 वर्षों के लिये) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹0 98.30 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

iv. Strengthening of spawn production and mushroom research unit to popularise the mushroom cultivation in U.P. परियोजना लागत ₹0 95.00 लाख:- एस.एल.एस.सी.ओ की विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना लागत ₹0 100.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई.सी.ए.आर. के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार द्वारा परियोजना की संशोधित कार्ययोजना आई.सी.ए.आर. को उपलब्ध कराते हुए अन्तिम अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा अन्तिम रूप से संशोधित कार्ययोजना लागत ₹0 95.00 लाख वर्ष 2017-18 हेतु वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹0 95.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 के लिए प्रदान किया गया।

v. Strengthening and modernization of seed testing laboratory for testing of seed samples of farmers and seed growers of U.P. परियोजना लागत ₹0 79.45 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में

विश्वविद्यालय की परियोजना लागत ₹० 80.00 लाख प्रस्तुत की गई थी। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई.सी.ए.आर० के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार द्वारा परियोजना की संशोधित कार्ययोजना आई.सी.ए.आर० नई दिल्ली को उपलब्ध कराते हुए अन्तिम अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में आई.सी.ए.आर० नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा अन्तिम रूप से संशोधित कार्ययोजना लागत ₹० 79.45 लाख (02 वर्षों के लिये) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹० 54.45 लाख के वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹० 79.45 लाख (02 वर्षों के लिये) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹० 54.45 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

- vi. Establishment and popularization of improved varieties/hybrids of vegetable and their agro-techniques to enhance vegetable production in U.P.** परियोजना लागत ₹० 63.00 लाख :— समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में विश्वविद्यालय की परियोजना लागत ₹० 63.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई.सी.ए.आर० के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। आई.सी.ए.आर० नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.10.2017 के द्वारा परियोजना के वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। तदनुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा परियोजना को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत ₹० 63.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान किया गया।
- vii. Seed storage godown for storage of leftover /carry over nucleus and breeder seeds of pulse crops** परियोजना लागत ₹० 97.00 लाख :— समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में विश्वविद्यालय की परियोजना लागत ₹० 97.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई.सी.ए.आर० के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। आई.सी.ए.आर० के पत्र दिनांक 20.11.2017 के द्वारा परियोजना के वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। तदनुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.12.2017 के द्वारा परियोजना को सपोर्ट किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत ₹० 97.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2017-18 हेतु प्रदान किया गया।
- viii. Scaling up of milk productivity through conservation of breed and nutritional management of small and marginal farmers of U.P.** परियोजना लागत ₹० 251.00 लाख :— समिति को अवगत कराया गया कि आई.सी.ए.आर० द्वारा परियोजना को सपोर्ट नहीं किया गया है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

2. सैम हिंगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, इलाहाबाद :-

i. Strengthening of Tissue culture facility for in vitro production of banana saplings to fulfills the demand of Allahabad and Kaushambi district परियोजना लागत ₹ 0 150.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में विश्वविद्यालय की परियोजना लागत ₹ 0 150.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई.सी.ए.आर. के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार द्वारा परियोजना की संशोधित कार्ययोजना आई.सी.ए.आर. को उपलब्ध कराते हुए अन्तिम अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में आई.सी.ए.आर. के पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा अन्तिम रूप से संशोधित कार्ययोजना लागत ₹ 0 150.00 लाख (02 वर्षों के लिये) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 0 145.00 लाख के वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹ 0 150.00 लाख (02 वर्षों के लिये) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 0 145.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. उ0प्रो पशुधन विकास परिषद, लखनऊ / पी.डी.डी.यू. मथुरा :-

i. Animal genetic disorder diagnostic and reproductive immunology laboratory परियोजना लागत ₹ 0 160.50 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक दिनांक 03.07.2017 में परियोजना लागत ₹ 0 160.50 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आई.सी.ए.आर. के अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तदक्रम में आई.सी.ए.आर. के पत्र दिनांक 23.08.2017 के द्वारा कार्ययोजना लागत ₹ 0 160.50 लाख (02 वर्षों के लिये) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 0 75.50 लाख के वित्त पोषण की संस्तुति कर दी गयी है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्ययोजना लागत ₹ 0 160.50 लाख (02 वर्षों के लिये) एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 0 75.50 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

6 अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से :-

I. पशुपालन विभाग :-

i. Additional Fodder Development Programme (AFDP) परियोजना लागत ₹ 0 432.00 लाख :- समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.08.2017 के द्वारा आर0के0वी0वाई0 की ए.एफ.डी.पी.-उपयोजना के अन्तर्गत प्रदेश के 02 से 03 वर्षों में सूखा प्रभावित जनपदों हेतु वर्ष 2017-18 के लिए निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र दिनांक 20.11.2017 के द्वारा ₹ 0 432.00 लाख की कार्ययोजना उपलब्ध करायी गयी, जिसे निदेशालय के पत्र दिनांक 22.11.2017 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित

किया गया। उपयोजना के अन्तर्गत 25 जनपदों में 7128 हेक्टेएर में चारा विकास कार्यक्रम संचालित किये जाने हैं। कृषकों को चारा उत्पादन किट हेतु ₹ 6000.00 प्रति हेक्टेएर की दर से अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.11.2017 के द्वारा इंगित किया गया है कि ₹ 432.00 लाख की धनराशि केन्द्रांश के रूप में ए.एफ.डी.पी. हेतु मात्राकृत की गयी हैं, जिसमें 40 प्रतिशत राज्यांश ₹ 288.00 लाख को समिलित करते हुए कुल ₹ 720.00 लाख की कार्ययोजना अपेक्षित है। तदक्रम में अध्यक्ष, एस0एल0एस0सी0 का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त कराने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत वर्ष 2017–18 हेतु ₹ 720.00 लाख की कार्ययोजना भारत सरकार की अपेक्षानुसार उपलब्ध कराते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त कराने की कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

II. यूपी0डास्प :-

- i. Crop Diversification Programme in original green revolution States (CDP) परियोजना लागत ₹ 3904.24 लाख :-समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.11.2017 के द्वारा आर0के0वी0वाई0 की सी.डी.पी.—उपयोजना हेतु वर्ष 2017–18 के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹ 3904.24 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है :—

धनराशि ₹ 0 लाख में

Intervention	AAP earlier approved	Revised AAP proposed by State Govt.	GoI approved on 60:40 sharing basis		
			Central	State	Total
Intervention proposed out of budget allocation during 2017-18	1226.66	1336.66	802.00	534.66	1336.66
Intervention approved during 2016-17 & to be implemented during 2017-18	Unspent balance	0.00	2530.46	1518.28	1012.18
	Interest earned		37.12	22.27	14.85
	Sub-total		2567.58	1540.55	1027.03
Grand total	1226.66	3904.24	2342.55	1561.69	3904.24

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सी.डी.पी.—उपयोजना हेतु वर्ष 2017–18 के एलोकेशन के सापेक्ष ₹ 1336.66 लाख एवं वर्ष 2016–17 की अप्रयुक्त धनराशि एवं उस पर आर्जित ब्याज

के विलम्ब रु0 2567.58 लाख कुल रु0 3904.24 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित भारत सरकार की अपेक्षानुसार क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्तानुसार एजेण्डा-5 एवं एजेण्डा-6 पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिये वित्त पोषण हेतु अनुमोदित परियोजनाओं एवं उपयोजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रु0 लाख में)

S. N.	Department	Project name	Stream	Duration	SLSC Approved Cost	
					Total cost	Cost for 2017-18
1	Agriculture	Pico-projectors and hand held devices for SMAE sub-mission of ATMA project	I	1	583.90	583.90
2		Scheme for promoting non-loanee farmers for Pradhan Mantri Fasal Beema Yojna in U.P.	P	1	100.00	100.00
3		Drip and sprinkler solar lift irrigation system for benefit of farmers in salty water affected area in Etah	I	1	78.34	78.34
4		Five days "Kisan Pathshala" at Gram Panchayat level	P	1	462.00	462.00
		Sub-total			1224.24	1224.24
5	Horticulture	Establishment of Hi-tech vegetable nursery to boost vegetable production	I	1	873.52	873.52
6		Development of bee-keeping in U.P.	I	1	1063.50	1063.50
7		Vegetable Initiatives for Urban Clusters (VIUC)	I	1	30.53	30.53
		Sub-total			1967.55	1967.55
8	Animal Husbandry	PPR vaccination in small ruminants	P	3	1421.24	353.75
9		Brucellosis vaccination in bovine	P	3	57.75	19.25
10		Glanders and Farcy disease surveillance scheme	P	2	327.39	190.56
11		Additional Fodder Development Programme (AFDP)	S	1	720.00	720.00
		Sub-total			2526.38	1283.56
11	SVBPUAT, Meerut	Establishment of advance diagnostic laboratory for identification of livestock diseases in Western U.P.	I	1	291.00	291.00
12		Establishment of goat unit for conservation and revitalization of superior germplasm of Barbari goat	I	1	141.00	141.00
		Sub-total			432.00	432.00
13	SHUATS, Allahabad	Development of barren and water scarce land through afforestation and agroforestry system in Allahabad district	I	3	171.00	93.70
14		Strengthening of Tissue culture facility for in vitro production of banana saplings to fulfills the demand of Allahabad and Kaushambi district	I	2	150.00	145.00
		Sub-total			321.00	238.70

S. N.	Department	Project name	Stream	Duration	SLSC Approved Cost	
					Total cost	Cost for 2017-18
15	CSAUAT, Kanpur	Role of lignocellulolytic bio-agents in decomposition of agro-residues to produce value added bio-fertilizer	P	1	50.00	50.00
16		Strengthening of vegetable research station, Kalyanpur, Kanpur	I	1	180.00	180.00
17		Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in UP.	P	1	37.10	37.10
18		Strengthening of Rabi cereal for development of high yielding wheat & barley varieties and their agro-techniques	I	2	163.30	98.30
19		Strengthening of spawn production and mushroom research unit to polarise the mushroom cultivation	I	1	95.00	95.00
20		Strengthening and modernization of seed testing laboratory for testing of seed samples of farmers and seed growers of U.P.	I	2	79.45	54.45
21		Establishment and popularization of improved varieties/ hybrids of vegetable and their agro-techniques to enhance vegetable production in U.P.	P	1	63.00	63.00
22		Seed storage godown for storage of leftover /carry over nucleus and breeder seeds of pulse crops	I	1	97.00	97.00
		Sub-total			764.85	674.85
23	BHU, Varanasi	Conservation of elite indigenous breeds of cows using modern techniques and surrogacy	I	3	2755.30	2000.00
24	PDDU Mathura	Establishment of semen analytical laboratory for semen certification quality assurance of breeding buck semen	I	1	169.00	169.00
25	PDDU/ UPLDB	Animal genetic disorder diagnostic and reproductive immunology laboratory	I	3	160.50	75.50
26	ICRISAT, Hyderabad	KJSAN-MITRA Knowledge-based Integrated Sustainable Agriculture Network- Mission India for Transforming Agriculture: Doubling Farmers Income in Bundelkhand, U.P.	P	3	2823.60	988.80
27	DASP	Crop Diversification Programme in original green revolution States	S	1	3904.24	3904.24
	Production and Growth				5342.08	2264.46
	Infrastructure and assets				7082.34	6069.74
	Sub-scheme				4624.24	4624.24
	Administrative (1% of Normal RKVY)				124.24	83.34
	Grand total				17172.90	13041.78

उक्तानुसार समिति द्वारा कुल लागत ₹0 17172.90 लाख एवं वर्ष 2017-18 हेतु ₹0 13041.78 लाख की परियोजनाएं अनुमोदित की गयी। समिति द्वारा आर.के.वी.वाई.-सामान्य की अनुमोदित परियोजनाओं के सापेक्ष प्रशासनिक मद हेतु 01 प्रतिशत धनराशि का अनुमोदन भी प्रदान किया गया।

बैठक संधन्यवाद समाप्त हुई।

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,

कृषि अनुभाग-3

संख्या - 1248 / 12-3-2017-199 / 2007

लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि, सह0 एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार, कृषि, सह0 एवं कृषक कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
5. सलाहकार, कृषि, नीति आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
11. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
16. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
17. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
18. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
19. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
20. प्रमुख सचिव, रेशम विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
21. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 लखनऊ।
23. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
24. कुलपति, नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
25. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

26. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
27. कुलपति, सैम हिंगन्बॉटम, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्यर टेक्नालोजी एण्ड साइंसेज, इलाहाबाद।
28. कुलपति, प० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
29. कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
30. निदेशक, आरोक्तोवीरोवाई०, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
31. निदेशक, गन्ना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
32. निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
33. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण, संस्था उ०प्र०, लखनऊ।
34. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
35. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
36. निदेशक, मत्स्य विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
37. निदेशक, रेशम विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
38. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
39. निदेशक, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो, मऊ।
40. निदेशक, एन०बी०आर०आई०, लखनऊ।
41. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी, संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ।
42. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
43. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ०प्र० शासन, लखनऊ।
44. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ०प्र० शासन, लखनऊ।
45. परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण परियोजना, उ०प्र० लखनऊ।
46. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
47. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
48. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०, लखनऊ।
49. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, लखनऊ।
50. नोडल अधिकारी रा.कृषि.यो., उ.प्र. कृषि भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

~~५६३~~
 (ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी),
 विशेष सचिव